



## बैंक ऑफ इंडिया (अग्रणी बैंक) के वित्तीय क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों का अध्ययन (इन्दौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. राकेश गिरवाल

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

शासकीय महाविद्यालय थांदला जिला झाबुआ

**सारांश :** प्रस्तुत शोध “बैंक ऑफ इंडिया (अग्रणी बैंक) की वित्तीय क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों का अध्ययन (इन्दौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)” बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका, विशेषकर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता तथा उसके क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इन्दौर जिले में कृषि, उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई ऋण एवं वित्तीय सुविधाओं के योगदान का मूल्यांकन करना है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े लाभार्थियों (कृषक, उद्यमी, व्यवसायी एवं योजना लाभार्थी) के सर्वेक्षण के माध्यम से तथा द्वितीयक आंकड़े बैंक की वार्षिक रिपोर्टों, अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों एवं प्रकाशित साहित्य से संकलित किए गए हैं। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय विधियों, विशेषकर ‘ANOVA (F-test)’ का प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई कृषि, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वित्तीय सहायता का उत्पादन, रोजगार, आय तथा जीवन-स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही, शासकीय एवं कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता ने लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। यद्यपि ऋण वितरण प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रक्रियागत बाधाएँ पाई गईं, फिर भी बैंक की भूमिका समग्र रूप से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने में प्रभावी सिद्ध हुई है। अतः यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि इन्दौर जिले के आर्थिक विकास में बैंक ऑफ इंडिया (अग्रणी बैंक) का योगदान महत्वपूर्ण है तथा नीति-स्तर पर प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

**कुंजी शब्द :-** बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक, वित्तीय क्रियाकलाप, ऋण वितरण, कृषि वित्त, औद्योगिक वित्त, व्यावसायिक वित्त, शासकीय योजनाएँ, आर्थिक विकास, इन्दौर जिला

### 1. प्रस्तावना :

बैंक देश की समस्त मौद्रिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था व साख व्यवस्था को संगठित व संचालित करते हैं। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है, जिसके बहुमुखी कार्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मुद्रा व साख की आवश्यकता पड़ती है, कुछ बचत करनी पड़ती है, कई तरह की आर्थिक सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है और ये समस्त आवश्यकतायें बैंक द्वारा ही पूरी की जाती हैं। एक मौद्रिक व्यवस्थापक के रूप में नोट के निर्गमन, वितरण व अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार उनका संतुलन बैंक का ही कार्य है। एक वित्त व्यवस्थापक के रूप में समाज के उन लोगों की बचतों को

एकत्र करने, जिनके पास अतिरिक्त धन है तथा जो उसका लाभपूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं जमा पर ब्याज देकर मितव्ययिता को प्रोत्साहित करते हैं और उनके अतिरिक्त धन का लाभपूर्ण विनियोग करते हैं।

एक साख व्यवस्थापक के रूप में वे देश में आवश्यकता के अनुसार साख का प्रसार व संकुचन करते हैं। बैंक मुद्रा का स्थानान्तरण कर न केवल अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी संतुलन स्थापित करते हैं। बैंक विनिमय विलेखों यथा चैक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के प्रयोग द्वारा धन के प्रयोग व संतुलन को अत्यधिक सरल व सुविधाप्रद बना देते हैं जिससे समाज की क्षमता व साधनों के प्रयोग में मितव्ययिता होती है और बैंकिंग आदतों का भी विकास होता है। आधुनिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक देश में वित्त की दिशा भी निर्धारित करते हैं। वे समाज में आर्थिक ईमानदारी व नैतिकता को प्रोत्साहित करते हैं। एक समुचित रूप में विकसित बैंकिंग व्यवस्था वाला देश आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ व सम्पन्न होता है। आर्थिक प्रगति की यह एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

## 2. बैंक ऑफ इंडिया का परिचय :

बैंक ऑफ इंडिया देश में विदेश में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सेन्ट्रल बैंक के बाद देश की चौथी बड़ी बैंक है। बैंक ने 1997 में पहली बार अपने अंश निर्गमित किये। दिनांक 30.09.2009 तक बैंक के कुल 2,15,790 अंशधारी हैं। दृढ़ता, विवेक और सावधानी की नीति का पालन करते हुए बैंक विभिन्न नवीन सेवाओं और प्रणालियों को शुरू करने के क्षेत्र में अग्रणी रहा। 31 मार्च 2021 तक, बैंक ऑफ इंडिया का कुल कारोबार ₹1,037,549 करोड़ (अमेरिकी डॉलर 140 बिलियन) है, भारत में बैंक ऑफ इंडिया की 5316 शाखाएं और 5,551 एटीएम हैं।

## 3. सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन :

अनुसंधान के विषय वस्तु के गहन अध्ययन के लिए श्रेष्ठ प्रकाशित साहित्य का अध्ययन एवं पुनर्नरीक्षण करना शोधकर्ता के लिए अति आवश्यक एवं लाभकारी होता है। बैंक की क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर क्रम अवरोही श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त शोध पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर प्रकाशित लेखा भी विधिवत समीक्षा की गई है।

## 4. शोध का उद्देश्य :

शोध अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य इन्दौर जिले के आर्थिक विकास में बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य योगदान से जुड़ी निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित है।

1. इन्दौर जिले के समग्र आर्थिक विकास में बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) के योगदान का अध्ययन।
2. इन्दौर जिले के कृषक, उद्यमी, व्यावसायी एवं बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा चलाई गई योजनाओं का अध्ययन करना।
3. इन्दौर जिले में बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) की वित्तीय उपलब्धियों का अध्ययन करना।
4. कृषि ऋणों का कृषि विकास पर प्रभावों का अध्ययन करना।
5. इन्दौर जिले में बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) के व्यापारिक स्थिति का अध्ययन करना।
6. इन्दौर जिले के विकास में बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) की विभिन्न योजनाएँ एवं नीतियों का अध्ययन करना।

## 5. शोध की अभिकल्पना :

1. इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त कृषि वित्त (ऋण) एवं उत्पादन, रोजगार एवं आय के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
2. इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त औद्योगिक वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार, आय एवं जीवन स्तर के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

3. इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त व्यवसाय वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार, आय एवं जीवन स्तर के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
4. इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के आय, रोजगार, जीवन-स्तर के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

## 6. शोध की पद्धति :

अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि का अनुशीलन किया जाता है। प्रस्तुत शोध प्ररचना वर्णात्मक है जो कि उपलब्ध सामग्री के अध्ययन पर पूर्णतः निर्भर है। शोध का मुख्य कार्य तथ्यों को संग्रहित करना होता है तथ्यों का संकलन यदि संकलित तथ्य अशुद्ध एवं पर्याप्त होते हैं तो अनुसंधान के निष्कर्ष भी भ्रमात्मक होते हैं वर्णन एवं अर्थों को यथा संभव मूल ग्रंथों पर आधारित करने का प्रयास किया जाये। अनुसंधान से संबंधित तथ्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं – (1) प्राथमिक (2) द्वितीयक स्रोत

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है शोध को मूर्त रूप देने के लिये पुस्तकालय पद्धति स्वैच्छिक, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, सरकारी दस्तावेज, प्रतिवेदन, विक्रम विश्वविद्यालय ग्रंथालय उज्जैन एवं अन्य ग्रंथालय सामग्री के आधार पर अध्ययन के आधार पर इत्यादि सामग्री का सहारा लिया गया है, जोकि हमें कोर्सवर्क के आधार पर शोध पद्धति का मार्गदर्शन दिया गया उसके आधार पर हम इस शोध कार्य में प्रस्तुत किया गया है।

भारत का हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है, जहाँ पर आर्थिक विकास अत्यन्त धीमी गति से हुआ है। राज्य के कुल 52 जिलों में से 8 जिले आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले हैं। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था 68 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के साथ पूर्णतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की लगभग 44 प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है। मध्यप्रदेश सोयाबीन, अलसी, दलहनों एवं चना का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में तिलहनों का यह दूसरा बड़ा तथा खाद्यान्न का तीसरा बड़ा उत्पादक है। समय के साथ औद्योगिकरण ने भी प्रदेश में अपनी जड़े जमाई है। देश के सीमेन्ट उत्पादन में 25 प्रतिशत कच्चे लोहे में 25 प्रतिशत इस्पात में 18 प्रतिशत अखबारी कागज में 32 प्रतिशत तथा एल्युमिनियम उत्पादन में 41 प्रतिशत का योगदान राज्य से होता है। हीरा, कोयला, बाक्साइट, मैंगनीज, डोलोमाइट के समूह भंडार राज्य में उपलब्ध है। संरचनात्मक कमियों के कारण राज्य अपनी क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं कर सका है।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) प्रदेश की जनता की विश्वसनीयता अर्जित कर चुका है, बैंक की कुल निक्षेप राशियों में मध्यप्रदेश का भाग 77.88 प्रतिशत है। बैंक राज्य की जनता की साख आवश्यकताओं को सर्वोत्तम प्राथमिकता देता है। बैंक द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों में मध्यप्रदेश में की गई साख, कुल साख का 63.38 प्रतिशत है। बैंक अपने ऋण एवं अग्रिम का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करता है। कृषि अग्रिम बैंक के शुद्ध ऋणों का 18.64 प्रतिशत है। बैंक लघु उद्योग, लघु व्यवसाय, समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता एवं अग्रिम देने में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एकीकृत विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण में बैंक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बैंक राज्य सरकार की कल्याणकारी विकास योजनाओं में सक्रिय वित्तीय सहयोग देता है।

विभिन्न वर्षों में बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) की निक्षेप राशियों एवं ऋण एवं अग्रिम राशियों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया गया है। पिछले दशक में निक्षेप राशियों में निरन्तर वृद्धि होती गई है, बैंक ने भी निक्षेप राशियों को आकर्षित करने की अनेक प्रेरक योजनाएँ विभिन्न वर्षों में जनता के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में निक्षेप राशियाँ बढ़कर क्रमशः 8475.37 करोड़ रुपये, 9757.35 करोड़ रुपये, 10867.74 करोड़ रुपये, 10927.50 करोड़ रुपये एवं 11996.38 करोड़ रुपये हो गई। बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण एवं

अग्रिम की राशियों का निक्षेप राशियों से विभिन्न वर्षों का प्रतिशत परिवर्तनशील रहा है। वर्ष 2018, 2019, 2020 एवं 2021 में यह प्रतिशत क्रमशः 51.46 प्रतिशत, 46.39 प्रतिशत, 50.26 प्रतिशत 50.54 प्रतिशत एवं 52.04 प्रतिशत रहा है।

शोध के इस वृहद कार्य में बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट, लेखा प्रपत्र, अनुसंधान रिपोर्ट, विशिष्ट पत्रिकाएं आदि मुख्य आधार रही। बैंक मुख्यालय इन्दौर आंचलिक कार्यालय इन्दौर, अग्रणी बैंक कार्यालय जिला इन्दौर एवं विभिन्न बैंक शाखाओं से समंक, जानकारीयां एवं सूचनाएं एकत्रित की गई है, समंकों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं। इन्दौर जिले के कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं शासकीय योजनाओं में बैंक के योगदान के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण भी किया गया, विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों से प्रश्नावलिया बनाकर जानकारी प्राप्त की गई है। इस अध्ययन को जड़, रुद एवं बंद अध्ययन से दूर रखकर वास्तविकता एवं मौलिकता प्रदान करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। इस विशद अध्ययन को पूर्ण करने के लिये न केवल सर्वेक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिया है अपितु इस विषय पर उपलब्ध साहित्य, सांख्यिकी, बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये समंकों का भी यथा स्थान समावेश किया है। जिन स्थानों पर साहित्य मौन है और समंक भी उपलब्ध नहीं है, वहां अनुभव और साक्षात्कार इस महायज्ञ को पूर्ण करने में सहयोगी रहे हैं।

इस शोध अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) ने इन्दौर जिले के कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सेवा क्षेत्र एवं शासकीय योजनाओं के विकास में अपनी वित्तीय सहायता द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसका अध्ययन एवं विश्लेषण करना है एवं बैंक अपनी वित्तीय गतिविधियों में वित्त पोषण द्वारा जिले के आर्थिक विकास में उपलब्धियाँ प्राप्त करने में कितना सफल हो सका है, इसका मूल्यांकन करना है। इन्दौर जिले के समग्र आर्थिक विकास में बैंक किस प्रकार से और अधिक योगदान दे सकती है, इन सम्भावनाओं का पता लगाना भी शोध का उद्देश्य रहा है।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपनी साख नीति के आधार के रूप में रखकर कृषि व्यवसाय में लगे लोगों को ऋण देने की अनेक योजनाएँ बनाई है। बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष ऋणनीति के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) कृषकों को कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन तथा कृषि में पूंजी निवेश कार्यों के लिये मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करते हैं। प्रत्यक्ष ऋण नीति में बिना किसी माध्यम के सीधे ही किसानों को कुआं, खाद, बीज, इंजिन, ट्रेक्टर, मोटर पम्प आदि के लिये ऋण स्वीकृत किये जाते हैं, अप्रत्यक्ष ऋण नीति में किसानों को सहकारी समिति और सहकारी संस्थानों के माध्यम से ऋण मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति में योगदान हेतु यह आवश्यक है कि कृषि के अतिरिक्त कृषि आधारित व्यवसायों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। अतः बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) पशुपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध उद्योग, मछली पालन उद्योग एवं गोबर गैस प्लांट हेतु भी आसान ऋण शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

शोधकर्ता ने इन्दौर जिले के बैंक ऑफ इंडिया के हितग्राही 100 कृषक परिवारों की उत्पादन क्षमता, आय, रोजगार एवं जीवन स्तर पर ऋण के प्रभाव का सर्वेक्षण किया है।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) देश के केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर औद्योगिक ऋण प्रदान करती है। बैंक ऑफ इंडिया लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर उदार शर्तों पर ऋण देती है एवं साथ ही वृहद उद्योगों के विकास हेतु भी सहायता प्रदान करती है।

शोधकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा प्रदत्त ऋण के 100 लाभगृहिता उद्यमियों का सर्वेक्षण किया है। जिनमें से 32 लघु उद्यमी, 58 मध्यम स्तरीय एवं 10 बड़े उद्यमी हैं।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) की वित्तीय सहायता से लाभान्वित व्यवसाय एवं सेवा कार्य में संलग्न सर्वेक्षित 100 व्यवसाय एवं सेवा कार्य में संलग्न व्यक्तियों के समूह में लघु एवं फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, परिवहन प्रचालक, सेवा कार्य में संलग्न व्यक्तियों, पेशेवर व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

शोधकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा विभिन्न शासकीय एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित 200 हितग्राहियों का सर्वेक्षण इन्दौर महू, सांवेर तथा देपालपुर आदि क्षेत्र के 50-50 हितग्राहियों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श के आधार पर किया गया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का हितग्राहियों के आय, रोजगार एवं जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से बैंक की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। बैंक अधिकारियों के कार्य में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं को जाँचा गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि बैंक द्वारा हितग्राहियों को कृषि ऋण प्रदान करते समय 80 प्रतिशत ऋण प्रकरणों में कृषकों की निरक्षरता एवं अज्ञानता की समस्या का सामना करना पड़ता है। 30 प्रतिशत प्रकरणों में प्रलेखों की अवधि सम्बंधी समस्या एवं भूमि तथा सम्पत्ति बेचने से उत्पन्न समस्या आती है, 40 प्रतिशत प्रकरणों में कागजी औपचारिकताएँ की पूर्णता हेतु सरकारी विभागों में आपसी समन्वय के अभाव के कारण ऋण स्वीकृति में देरी होती है। इन समस्याओं के अतिरिक्त ऋण की उचित सीमा राशि का निर्धारण करने में एवं कृषकों की अनुदान राशि देरी से प्राप्त होने की समस्या भी आती है। औद्योगिक ऋण स्वीकृत करते समय आने वाली समस्याओं में 70 प्रतिशत प्रकरणों में उद्यमी द्वारा अपूर्ण परियोजना लागत प्रतिवेदन प्रस्तुति होती है, उसमें नवीन योजना का अभाव होता है, 50 प्रतिशत प्रकरणों में आवश्यक तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव की कमी पाई जाती है, 30 प्रतिशत प्रकरणों में उचित सर्वेक्षण का अभाव पाया जाता है। व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के ऋण प्रदान करने में बैंक की बाधाओं में 60 प्रतिशत प्रकरणों में उचित ग्यारन्टी की समस्या आती है 50 प्रतिशत प्रकरणों में ऋण प्राप्तकर्ताओं में योग्यता एवं पात्रता का अभाव पाया जाता है, 30 प्रतिशत प्रकरणों में उचित परियोजना के अभाव के कारण ऋण के दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है, जिसके कारण ऋण वसूली में दिक्कतें आती है।

## 7. अभिकल्पनाओं पर आधारित निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा इन्दौर जिले में प्रदत्त कृषि वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार एवं आय पर प्रभाव का परीक्षण करने के लिए (F test) एफ परीक्षण का उपयोग कर (ANOVA) प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई। वर्तमान अध्ययन में क्षेत्र की दो श्रेणियों यथा पुरुष एवं महिला में विभक्त किया गया। प्रस्तुत विश्लेषण के लिए विभिन्न आंकड़ों समूहों में प्रसरण के अन्तर को दो वर्गों प्रथम प्रतिदर्शों के मध्य प्रसरण एवं द्वितीय प्रतिदर्शों के अन्तर्गत प्रसरण में बाँटकर, प्रसरण अनुपात ज्ञात किया गया। क्षेत्र की दो श्रेणियों के आधार पर उत्तरदाताओं के औसत आंकड़े प्राप्त करने के लिए मानक विचलन मान प्राप्त किया गया। प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार पर उत्पादन पर प्रभाव का मान (.000), रोजगार पर प्रभाव का मान (.000), आय पर प्रभाव का मान (.000) एवं जीवन स्तर पर प्रभाव का मान (.010) प्राप्त हुआ। चूँकि प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार प्राप्त P मान 0.05 से कम है इसलिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा इन्दौर जिले में प्रदत्त कृषि वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार एवं आय पर प्रभाव पड़ रहा है, सार्थक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त कृषि वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार एवं आय पर प्रभाव पड़ रहा है और अधिक प्रभाव के लिए शासकीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा इन्दौर जिले में प्रदत्त औद्योगिक वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार एवं आय पर प्रभाव का परीक्षण करने के लिए (F test) एफ परीक्षण का उपयोग कर (ANOVA) प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई। प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार पर उत्पादन पर प्रभाव का मान (.000), रोजगार पर प्रभाव का मान (.032), आय पर प्रभाव का मान (.043) एवं जीवन स्तर पर प्रभाव का मान (.001) प्राप्त हुआ। चूँकि प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार प्राप्त P मान 0.05 से कम है इसलिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा इन्दौर जिले को प्रदत्त औद्योगिक वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार, आय एवं जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ रहा

है, सार्थक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त प्रदत्त औद्योगिक वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार, आय एवं जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है और अधिक प्रभाव के लिए शासकीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा इन्दौर जिले में प्रदत्त व्यवसाय वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार एवं आय पर प्रभाव का परीक्षण करने के लिए (F test) एफ परीक्षण का उपयोग कर (ANOVA) प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई। प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार पर उत्पादन पर प्रभाव का मान (.000), रोजगार पर प्रभाव का मान (.037), आय पर प्रभाव का मान (.000) एवं जीवन स्तर पर प्रभाव का मान (.015) प्राप्त हुआ। चूँकि प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार प्राप्त P मान 0.05 से कम है इसलिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा इन्दौर जिले में प्रदत्त व्यवसाय वित्त (ऋण) का व्यवसाय, रोजगार, आय एवं जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, सार्थक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त प्रदत्त व्यवसाय वित्त (ऋण) का उत्पादन, रोजगार, आय एवं जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है और अधिक प्रभाव के लिए शासकीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के आय, रोजगार, जीवन-स्तर पर प्रभाव का परीक्षण करने के लिए (F test) एफ परीक्षण का उपयोग कर (ANOVA) प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई। प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार पर उत्पादन पर प्रभाव का मान (.036), रोजगार पर प्रभाव का मान (.047), आय पर प्रभाव का मान (.033) एवं जीवन स्तर पर प्रभाव का मान (.013) प्राप्त हुआ। चूँकि प्रसरण विश्लेषण की गणना के आधार प्राप्त P मान 0.05 से कम है इसलिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के आय, रोजगार, जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, सार्थक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्दौर जिले में बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के आय, रोजगार, जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है और अधिक प्रभाव के लिए शासकीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

## 8. सुझाव :

प्रस्तुत शोध कार्य में बैंक ऑफ इंडिया की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्याओं का गहन विवेचन किया गया है एवं तत्सम्बन्धी सुझाव भी दिये गये हैं। कृषकों की ऋण संबंधी समस्याओं के निदान हेतु बैंक द्वारा समय-समय पर प्रत्येक ग्राम में ऋण शिविर लगाकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर ऋण योजनाओं की जानकारी दी जाए, उनके ऋण प्रकरण वही पर तैयार कर तुरन्त स्वीकृत किये जाये, इस शिविर में अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी आमंत्रित किये जाये ताकि कागजी औपचारिकताओं की भी तुरन्त पूर्ति की जा सके। विभिन्न कृषि कार्यों हेतु निर्धारित ऋण राशि में वृद्धि की जानी चाहिए, किसानों को ऋण हेतु स्टाम्प फीस से मुक्ति दी जानी चाहिए, सरकारी विभागों द्वारा कृषकों को अनुदान राशि का तुरन्त भुगतान किया जाना चाहिए। भू-रक्षण समिति को चाहिए कि बदलते पर्यावरण के संदर्भ में वह जिला स्तर पर दुवारा सर्वेक्षण कराए नई रिपोर्ट प्रकाशित करे। शासन द्वारा कृषकों को निर्वाध विद्युत पूर्ति की जानी चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप आदि के समय शासन एवं बैंक द्वारा कृषकों को विशेष राहत प्रदान की दूर की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के स्वास्थ्य परिक्षण हेतु पशु चिकित्सकों की कमी पूरी की जाये, दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। मस्त्य पालन मधुमक्खी पालन, शूकर पालन आदि के संबंध में कृषकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। उद्यमियों एवं व्यवसायियों द्वारा शासकीय नियमों को ध्यान में रखकर नवीन योजना बनाकर बैंक ऑफ इंडिया, (अग्रणी बैंक) से आसानी से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना लागत प्रतिवेदन आवश्यक प्रपत्रों सहित बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उद्यमी को उद्योग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान पूर्व में ही प्राप्त कर लेना चाहिये।

इससे उसे स्वयं उद्योग के संचालन में सुविधा होगी। बैंक भी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति को सरलता से ऋण प्रदान करती है। व्यवसायियों को भी बैंक आवश्यक औपचारिकताओं के उपरान्त तुरन्त ऋण स्वीकृत करती है। व्यवसायी द्वारा उचित ग्यारन्टी की व्यवस्था की जानी चाहिए। बैंक की पात्रता एवं योग्यता संबंधी नियमों की पूर्ति करनी चाहिए। बैंक को अपनी योजना का विश्वास दिलाकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। बैंक द्वारा भी अपनी ऋण स्वीकृति की जटिलताओं को कम करके कागजी औपचारिकताओं को कम करना चाहिए, केवल अति आवश्यक प्रमाण-पत्रों की माँग ही करना चाहिए, ब्याज दरों में कमी करना चाहिये, ऋण राशि की पूर्ति तुरन्त करना चाहिए ताकि ऋण प्राप्तकर्ता उसका सदुपयोग शीघ्रता से कर सके, बैंक को अपनी ग्राहक सेवाओं में सुधार करना चाहिये।

### सन्दर्भ

1. Bank of India. (2021). *Annual report 2020–21*. Bank of India.
2. Bank of India. (2020). *Lead bank scheme: District credit plan – Indore district*. Bank of India.
3. Government of India. (2005). *The Disaster Management Act, 2005*. Ministry of Law and Justice.
4. Government of India. (2019). *Economic survey of India 2018–19*. Ministry of Finance.
5. Government of India. (2021). *Statistical handbook of Madhya Pradesh*. Directorate of Economics and Statistics.
6. Reserve Bank of India. (2020). *Handbook of statistics on the Indian economy*. Reserve Bank of India.
7. Reserve Bank of India. (2021). *Report on trend and progress of banking in India*. Reserve Bank of India.
8. Reserve Bank of India. (2022). *Master directions on priority sector lending*. Reserve Bank of India.
9. Sharma, R. K., & Gupta, S. (2018). *Banking and finance in India*. Kalyani Publishers.
10. Singh, K., & Kaur, G. (2017). Role of commercial banks in regional economic development in India. *International Journal of Banking and Finance*, 9(2), 45–58.
11. Thakur, D., & Jain, R. (2019). Agricultural credit and rural development in India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 74(3), 321–334.
12. World Bank. (2020). *Financial inclusion and economic growth: Evidence from developing economies*. World Bank Publications.